THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a) to (c) The project proposal for installation of tubewells under River Lift Project in Balasore, Cuttack and Puri districts of Orissa costing Rs. 51 crores (1989 price level) was posed for German assistance. The project envisages installation of 150 numbers Lift Schemes (100 numbers from Greeks and 50 on Rivers) for creating irrigation potential of 6,000 hectares in kharif and 6,000 hectares in rabi through the former and 10,000 hectares through the latter on rivers like Subarnarekha, Budhabalanga, Baitarni, Bhehmani and Mahanadi and tributaries. The project has been posed for a German assistance of 55 million Deutsche Marks. Agreement has not been signed and further development are awaited.

**Central assistance for drought situation in Bihar**

796. SHRI GAYA SINGH :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the State Government of Bihar has submitted a memorandum to the Central Government seeking assistance of Rs. 1,117 crore to fight severe drought situation in the State; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) and (b) State Government of Bihar has submitted Memoranda seeking Central assistance of Rs. 1200.12 crores for relief measures in the areas affected by drought during the current year. The request of the State Government was considered in the light of existing scheme for financing relief expenditure. Based on the report of the Central Team and recommendations of the Inter-Ministerial Group (IMG), 4th quarterly instalments of Central share of Calamity Relief Fund (CRF) for the year 1992-93 and 2 quarterly instalments for the year 1993-94, totalling to Rs. 19.6875 crores have been released, in advance, to the Government of Bihar.

**C.A.C.P. recommendations on wheat price**

797. SHRI N. E. BALARAM :
SHRI N. GIRI PRASAD :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission for Agricultural Costs and Prices has recommended the prices of wheat at Rs. 300/- per quintal; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) and (b) The Report of the Commission for Agricultural Costs and Prices on Rabi Crops of 1992-93 including Wheat is at present under consideration of the Government.

**Income Tax on agricultural income**

798. SHRI PASUMPON THAKIRUTTINAN :
SHRI V. GOPALSAMY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the issue of income tax on agricultural income was discussed in the special meeting of the Indian Council of Agriculture Research held at Hyderabad; and

(b) if so, what important decisions were taken in that meeting ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA) : (a) Yes, Sir.

(b) A reference was made to the Chelliah Committee report on taxes as to who will decide for the purpose of levying income tax on the people who are in farming and not in business and *vice-versa*. A need for clearly defining this was emphasised and for differentiating a farmer having ancestral land depending on agriculture for generations, from the one who had no land in 1950's and bought land to safeguard himself.

Majority of the members who expressed their opinion on this wanted farmers to be kept outside the dragnet of income-tax so that farmers can devote their time and energies for doing farming.

**कृषि क्षेत्र को राज सहायता**

799. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अनेक विकासशील और विकसित देशों में कृषि क्षेत्र को राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूगोस्लाविया तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य यूरोपीय देशों में कितने-कितने प्रतिशत राज सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में राजसहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) जी, हां ।

(ख) उर्वरक समाचार (फर्टिलाइजर न्यूज) सितम्बर, 1992 के अनुसार, 1990 में कृषि उत्पादन के मूल्य की तुलना में राजसहायता की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :—

| देश | कृषि उत्पादन के मूल्य की तुलना में प्रतिशतता |
|---|---|
| जापान | 68 |
| यूरोपीय समुदाय | 48 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 30 |
| कनाडा | 41 |
| आस्ट्रेलिया | 11 |

(ग) और (घ) सरकार की नीति का उद्देश्य वित्तीय असंतुलन घटाने की दृष्टि से कृषि सहित अर्थव्यवस्था में राजसहायता का स्तर कम करना है ताकि विकास संबंधी कार्यकलाप गैर-मुद्रा स्फीति तरीके से वित्त पोषित की जा सके । तदनुसार उर्वरकों पर राजसहायता कम की गई है । तथापि कृषकों को बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है ।

**कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि**

800. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन लागत में प्रति हेक्टेयर चार सौ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डीजल की कीमतों में वृद्धि तथा विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत प्रभार बढ़ाये जाने के कारण कृषि उत्पादन लागत में और अधिक वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त वृद्धियों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इस वर्ष उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि लागत में वृद्धि का प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा हाल ही में पोषित रियायतों के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई लागत में कितने प्रतिशत कमी होने का अनुमान है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)** : (क) विभिन्न उर्वरकों की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं और धान की विभिन्न फसलों की प्रति हैक्टेयर खेती की लागत 100 रुपये से 250 रुपये बढ़ने की संभावना है । कीमत में वृद्धि उर्वरकों के उपयोग स्तर और कुल उर्वरकों में एन. पी. के. के अनुपात पर निर्भर करेगी । मोटे अनाज, दलहन और कपास जैसी सिंचित फसलों के मामले में जहां उर्वरकों का उपयोग काफी कम